pro-active, not reactive. I want to icnow whether this pro-active job was being done; if it was not being done, whether he will kindly do it and inform the House what type of study or exploration was done to merge such a sick Company with another profit-making company under the same Coal India. You can have some relief of tax also for the industrial company. Would you kindly examine it? Or, have you examined it?

SHRI DILIP RAY: Sir, as a result of the net-worth becoming negative in BCCL and ECIL, BCCL was referred to BIFR in 1996-97 and ECIL in 1997-98. But with the conversion of debt worth Rs. 9% crores in BCCL and Rs. 1,180 crores in ECIL into equity, the net-worth has again become positive, and of course, BCCL has come out of the BIFR, and, of course, ECIL will also come out of the BIFR. We are just waiting for the awards.

SHRI DIPANKER MUKHERJEE: It should not have been referred to BIFR. Without going into the option of seeing whether it can be merged with the healthy company under the same Coal India, the question of referring it to the BIFR should not have arisen. That is what I am asking.

SHRI DILIP RAY: Sir, regarding this tax factor, I will look into it.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Mr..Chairman, Sir, through you, I would like to ask the Minister a question arising from his reply: "The question of the structure of the coal companies in India has been considered by the Government several times." Sir, is the Coal India enjoying the worst form of monopoly all over the world. The price is being fixed by them, the quality is being determined by them, and in the process, the consumer is the worst sufferer. In our Dhanbad fields, 33,000 workers are involved in the SSI sector producing coke without any authority, a service charge of eighty rupees has been imposed. My own feeling is that Coal India is a deadwood and it should be discarded; otherwise, the cost is increasing every day, the quality is deteriorating and the price is increasing. Would the Minister tell me what the function of Coal India as such in promoting the coal development, coal resources, pricing, quality etc.?

SHRI DILIP RAY: Sir, this Coal India is an umbrella organisation of all the subsidiaries looking after the coal production, planning, marketing, linkages and distribution. That is the basic work of Coal India, and all the subsidiaries are independent enough to look after their day-to-day affairs.

Grouping of SCs in A and B Category in Haryana

*563. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from Associations or M.Ps against the grouping of Scheduled Castes in the A and B category for appointment in services and the admission in Training Institute in Haryana;

(b) if so, the details thereof and the action taken by the Central Government;

(c) whether it is also a fact that the grouping of A and B in the Scheduled Castes category is ultra vires of Article 341 of the Constitution and void; and

(d) if the answer to (c) above be in the affirmative, what acction Government are going to take against this and if not, the reasons therefor as there is no grouping in the STs, OBCs and General category?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Constitution (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order 1950) as amended under Article 341(1) of the Constitution dotw not envisage any categorisation (sub-elassification) of the Scheduled Castes for the purpose of reservation. As per clause (2) of Article 341, only the Parliament has power of make modification in the list of Scheduled Castes specified by the President under Article 341(1).

(d) Under constitution of India, the Supreme Court and the High Courts have jurisdiction to declare any law or executive action ultra vires of any provision *ol* the Constitution and void.

श्री गांधी आजाद:सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसके संबंध में मेरा प्रश्न यह था कि यह सच है कि अनुसूचित जातियों को "क" और "ख" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लघंन है तथा अमान्य है। इसका सीधे-सीधे उत्तर येस या नो में आना चाहिए, लेकिन माननीया मंत्री जी द्वारा जो यह उत्तर पढ़ा गया है उसमें राष्ट्रपति के अधिकार और संसद के अधिकार को उद्धत किया गया है। मैं आपके माध्यम से एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 जिसका उत्तर 6 जुलाई के माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में रखा गया था उसको उद्धत करना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों को समूह "क" "ख" "ग" तथा "घ" में समूहबद्ध करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। किन्तु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आंध्र प्रदेश सरकार का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 341 के अधिकार के परे तथा व्यर्थ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की थी। तथापि, अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन 10.2.98 तथा 11.2.98 को आंध्र प्रदेश सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायलय से अपनी अपील वापिस ले ली"।

मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि जब 341 के अनुसार किसी भी सरकार द्वारा यह संविधान का उल्लघंन है तो मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार की ग्रुपिंग संविधान के विरुद्ध है तो ऐसी ही ग्रुपिंग हरियाणा और पंजाब सरकार द्वारा क्यों की जा रही है? मेरा पूरक प्रस्न "ख" यह है कि इस प्रकार की ग्रुपिंग करने वाली प्रांतीय सरकारों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कोई हस्तक्षेप या कार्यवाही की जा रही है?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, the question was whether we had received any representation from Members of Parliament or any associations that Haryana had done such grouping. We have not received any representations of any kind. Therefore, the q^uestion of taking action against the State Government doesn't arise.

Secondly, he is quite true that it is *ultra vires* the Constitution. I have assured about it.

श्री जनार्दन यादव: सभापति, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार में जो ओ.बी.सी को आरक्षण मिला है वह एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 में विभाजित है और आरक्षण में इसके आधार पर लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जब कि 341 में जिनको आरक्षण मिला है, उनका क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बिहार में चल रहा है एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 इसके बारे में मंत्री महोदया का क्या कहना है?

श्री रामजीलाल: धन्यवाद, सभापति महोदय। संविधान के अनुच्छेद 341 के अनतर्गत तथा संशोधित संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण की दृष्टि से यह बात ठीक है। महोदय, में आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके उत्तर से साफ जाहिर है कि संविधान के मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने उन विशेष जातियों—अनुसूचित जाति और जन-जातियों की कुछ विशेष जातियों, जिनका बहुमत है और जो आज तक आरक्षण का लाभ उठाते रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर—जब उनके पास लोगों के डेपूटेशन आए, रिप्रजन्टेशन आए कि कुछ लोग ही, जो शैड्यूल्ड कास्ट और दूसरी जातियों के हैं उन्हीं को इसका लाभ मिल रहा है और दूसरी छोटी जातियों को पिछले 48 सालों में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला तो हरियाणा सरकार ने "क" और "ख" श्रेणी बनाकर, "ए" और "बी" कैटेगरी बनाकर, दो साल पहले या तीन साल पहले यह किया। 341 का तो मुझे ज्ञान नहीं है। इस बारे में मंत्री जी ने अभी कहा है। लेकिन उन लोगों को, जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन जातियों और अन्य जातियों का कोटा 50-50 किया गया। 50 परसेंट विशेष जातियों के लिए और 50 परसेंट दूसरी जातियों, शैड्यूल्ड कास्ट और अन्य जातियों के लिए किया। उनका बहुमत देखकर सरकार ने 50 परसेंट किया या नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन उन लोगों की आरक्षण के अंदर नुमाइन्दगी सरकार ने की थी।

श्री सभापति: आप जवाब दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं।

श्री बंगारु लक्ष्मण: सर, यह आपको भी जानकारी होगी कि आंध्र प्रदेश में कैटगराइजेशन को लेकर आंदोलन हुआ था और सरकार ने ए,बी,सी,डी, चार कैटेगराइजेशन किए थे। जिस जवाब का जिक्र मंत्री जी ने किया है, 6 जुलाई के जवाब का उसको अगर माना जाए तो सरकार इस निर्णय पर पहुंच गई कि इस प्रकार का जो भी कैटेगराइजेशन होगा वह आर्टिकल 341 का आल्ट्रावाइरस होगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि इस कैटेगनाइजेशन को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अल्ट्रावायर्स है आफ आर्टिकल 341। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि यह मामला नेशनल कमीशन फार शैड्यूल्ड कास्ट्स

और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने जाना चाहिये और उनकी राय ले कर के इसमें कैटेगराइजेशन हो सकता है, यह बात हाई कोर्ट ने कही। मामला आज नेशनल कमीशन के सामने हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले 50 साल से इस रिज़र्वेशन की नीति के चलते जो अनुभव सामने आए हैं, आज यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के अन्दर ऐसी कई कम्युनिटीज़ है जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है और वे आन्दोलित हैं अति पिछड़ों के नाम से आर कई नामों से। उनका रिज़ेंटमेंट बढ़ता चला जा रहा है और एजीटेशन होता जा रहा है कि हमें कोई रिज़र्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। उसी प्रकार से ट्रावल्स के अन्दर जो हिली एरियाज़ में हैं, प्लेंस में ट्राइबल रहते हैं, इसके अन्दर बहुत सी बातें हैं, काफी डिसाक्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर क्या सरकार इस पर पूरी तरह से विचार करेगी और इस रिज़र्वशन का लाभ उसमें आने वालों को सब को मिले और जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको अभी तक फायदा नहीं मिला है, उनको किस प्रकार से यह लाभ दिया जाए। आखिर रिज़र्वेशन सोशल जस्टिस के आधार पर हुआ है, सोशल जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए सरकार क्या इस दृष्टि से विचार करेगी और क्सी निषकर्ष पर पहुंचेगी? यह मेरा सवाल है।

SHRIMATl MANEKA GANDHI: Sir, it is true that certain communities, in spite of being reserved, have not received the benefits which they are supposed to have. But that is really a function of unequal development. There are areas and pockets of poverty all over India.

There are some districts and constituencies which are much more backward than others. I think this would have been planned in the same way. When it comes to the question of due share of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we have not done badly. We have managed to reach a total of 18 per cent in some cases where Scheduled Castes and Scheduled Tribes have received their due share. Now if a particul?r tribe or a caste or a sub-caste fears that it has not been given it due share, they can make a representation. We will look into that matter.

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षित कोटे में जो बहुत पिछड़े बालमीकि समुदाय के लोग हैं, उनको प्रशासनिक सेवाओं में अवसर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति के बाल्मीकि समुदाय के लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वह बहुत कम मिल रहा है और प्रशासनिक सेवाओं में अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। यह आपके संज्ञान में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के इस आरक्षित कोटे के अन्दर सरकार बाल्मीकि समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कर रही है?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, there is no particular reservation or quota for one particular caste. There is a general quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If one is eligible for it, that can be done.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Sir, the Government of Andhra Pradesh wrote to the Commission for Scheduled Castes and Schedules Tribes to allow them categorisation of SCs in Andhra Pradesh in 'a', 'b', 'c' and 'd'. I would like to know from the hon. Minister whether the Government would take steps to request the Commission to expedite the matter in order to stop the agitation in Andhra Pradesh.

SHRIMATI MANEKA GANDHI; Sir, I am aware of this agitation. I have requested the Chairman of the Commission several times to reach a decision. I think it is a far more complicated matter than merely declaring it. Since they have lost the case in the High Court and since it has been declared *ultra vires* the Constitution, it now has to come to the Commission for further review.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it was not declared *ultra vires* the Constitution. This will send a wrong signal and there will again be an agitation. They have only said that the procedure adopted for finalising categories was not within the Constitution and that it has to be referred to the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and then after taking the view of the Commission, the Government should do it. But it seems that the hon. Minister has not been properly informed about it. Sir, this was the finding of the High Court. Sir, I request the hon. Minister to study it and then proceed further; otherwise, it would send a wrong signal. I have a copy of the Constitution with me. Nowhere is it stated therein that there should not be any categorisation.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, the Andhra Pradesh Government filed an appeal against this order in the Supreme Court. But it

withdrew the scheme after losing the case that they could not categorise as (a), (b), (c) and (d). Did it not lose the case? (Interruptions)

SHRI BANGARU LAXMAN: That is not the case. The Supreme said that this should go to the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and that the Commission's opinion should be obtained before arriving at this kind of categorisation. So, when the Andhra Pradesh Government went before the Supreme Court, it simultaneously went before the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well. The Commission insrsted that when the appeal ^*as* pending before the Court, they would not be able to go into the question. So, the Andhra Pradesh Governmeni: withdrew the appeal from the Supreme Court and has left the matter to the National Commission for Scheduled Castes and Schcdul<xl Tribes. Please study the case.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: We have studied the case. We are looking into it sympathetically. We have had several meetings on this. It is for the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to take a view on this which they have not done so far in spite of our repeated requests.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Veena Verma... *{Interrup tions)*

SHRI BANGARU LAXMAN: A lot of agitations are going on.

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं माननीय मंत्री जे से पूछना चाहूंगी कि जब महिला आरक्षण की बात हर तरफ उठ रही है और महिलाओं के जातीय आधार पर आरक्षण की बात राजनीति में लोक सभा, विधान सभाओं में भी उठ रही है तो क्या आपके मंत्रालय ने नेशनल हुमेन राइट्स कमीशन को कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि महिलाओं को भी नौकरी में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए? इस तरह का भेजा है या आप भेजेंगी? हमारी तो यह मांग है कि महिलाओं का भी नौकरियों में भी जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या इस पर विचार करेंगी?

SHRIMAn MANEKA GANDHI: We have made no such requests *Interrup tions)*It does not come under my ambit at all.

DR. y. RADHAKRISHNA MURTHY: Sir, again referring to the problem of Andhra Pradesh, it is clearly stated a»d we understand the problem that Parliament alone has the power to make modifications in the list of Scheduled Castes and Scheduled Trrbes specified by the President under article 341 of the Constitution. But the point here is about categorisation and not about enlarging or decreasing the numbers in the list. The Minister has not been able to tell us regarding this thing. Secondly, I would like to know whether there has been any representation from any other State Government on this. If so, I would like to know whether the Government is thinking of taking this problem before parliament if parliament is the only authority that can change this. A lot of agitations are going on and sometimes there are violent agitations. It becomes a law and order problem in Andhra Pradesh. I would like to know whether the Government is thinking in terms of taking it before Parliament by whichever procedure has been set for this. The Government should be knowing the procedures. Sir, I don't want any cryptic and philosophical answer. I want a straight answer.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, there has been no reprsentation frorn any Government apart from Andhra Pradesh regarding declaration of (a), (b), (c) and (d) categories. This categorisation will lead to far more violent agitations by those Scheduled Castes who believe that they have been pat into a particular category which is unfair to them. It will really open another Pandora's bex where everybody would want to be in Category (a) of the Scheduled Castes or Category (b) of the Scheduled Castes if it meant more reservation of seats. Are you prepared to go into yet another controversy like that? Or shall we see it first? We have 1,400 or so application *....{Interruptions)*

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद: आपने कहा है कि आपने कमीशन को लिखा है ...(**व्यवधान**) अनेक बार आपने कमीशन को कहा है कि क्या हुआ है...(**व्यवधान**)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There can bs categorisation of backward dasses as (a), (b), (c) and (d) under the Constitution. Article 341 (2) clearly says and I quote: "Parliament may be law include in or exclude from the list

of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part pf or group within any caste, race or tribe,but save as aforesaid a notificationissued under the said clause shall be varied by any subsequent notification." This being the Constkutional provision, there is no question of violating the Constitution. There should be categorisation of backward classes because equitable justice should be made. There are sections of people in Andhra Pradesh and other parts of the country who are feeling that even though they constitute 40 per cent, their representation in services and their tepresentalion in other categories of employment is only 15 per cent or 20 per cent.

It is only 15% or 20%. That is why there is agitation, there is violence. I am not asking the Minister to straightaway say 'Yes'. But let the Government study this entire complex issue, keeping in view the repercussions whatsoever, the request of the State Government of Andhra Pradesh and also the representations received from other communities. The National Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is already going into the matter. Let the Government not foreclose the option and say 'no' to this, because it will rake up ... *(Interruptions)*

SHRI BANGARU LAXMAN: Sir,...

MR. CHAIRMAN: Please sit down now.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: I have not taken a stand in the matter. The fact that this sparks off a debate here, which is so heated, is a forerunner. I am happy to follow any suggestion. That is the reasons why we have a National Commission. It is the duty of the National Commission to study this subject seriously and 1 am sure they are doing an excellent job. The nwtnent they tell us what to do, we will be happy to do it.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति महोदय, संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लिखी गई है और अनुसूचित जातियां कौन हैं, अनुसूचित जनजातियां कौन हैं, इनकी सूची राज्यवार संविधान में दी गई है। यह सही है कि कुछ जातियां शामिल की जाती हैं और कुछ जातियाम निकाली जा सकती हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या अनुसूचित जाति, जनजातियों में से फिर उप जातियों के नाम पर आरक्षण देना क्या यह संवैधानिक होगा या गैर संवैधानिक होगा?

SHRIMATl MANEKA GANDI: *I* don't think this question can be answered that sirrtply.

SHRI S.R. BOMMAI: There has been an agitation in this country that reservations for SCs and STs are being enjoyed by a particular class. Particularly, the rural backward, fwor Scheduled Castes are not getting the benefits. It is said that certain families have monopolised it. Therefore, a suggestion has been floated in the country, a debate is going on, that an econmic criterion should be applied to Scheduled Castes, without categorising them into A,B,C, or D categories. I would like to know whether the Government will consider it.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: This is an excellent suggestion. If it were left to a few people, perhaps it could have been done. Unfortunately, it has not been considered.

MR. CHAIRMAN: Question Number 564.

श्री चुन्नी लाल चौधरी: माननीय सभापति जी, इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं?

श्री सभापति: कौन सा हैं?

श्री चुन्नी लाल चौधरी: इसी आरक्षण के ऊपर है।

श्री सभापति: वह सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल सामने आ गया है।

श्री चुन्नी लाल चौधरी: बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री सभापति: अब सवाल हो गया।

Development of Trade in the North-Eastern region

*564. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) tbe details of schemes formulated by Government for implementation during Ninth Plan in N.E. Region towards development of trade activities;

(b) the details of on-going projects inchiding their location and present status;

(c) whether Government propose to formulate any comprehensive export-import policy for N.E. Region;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and